



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

DOI : 03.2021-11278686

ISSN : 2582-8568

IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का उत्पादन प्रणाली पर प्रभाव (Agrarian Economy and Mode of Production in India)

डॉ. प्रवेश कुमार (पाण्डेय)

असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग,

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज,

एटा (उत्तरप्रदेश)

E-mail: praveshkumarpandey1971@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686

DOI Link :: <https://doi-ds.org/doilink/02.2022-25738458/IRJHIS2202006>

प्रस्तावना :

कृषि समस्त उद्योगों की जननी, मानव जीवन की पोषक, प्रगति की सूचक तथा सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है। तीव्र अर्थिक विकास की ओर उन्मुख वर्तमान गतिशील विश्व के समस्त विकसित एवं विकासशील देश अपने उपलब्ध संसाधनों को अपनी परिस्थितियों एवं क्षमताओं के अनुरूप यथासम्भव अनुकूलतम उपायोग कर कृषि उत्पादों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार तथा प्रगतिशील एवं व्यावसायिक कृषि के विकास हेतु सचेत एवं सतत् प्रयासरत है। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय होने के साथ-साथ कृषि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत, रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन औद्योगिक विकास वाणिज्य एवं व्यापार का आधार है। गरीब एवं विकासशील राष्ट्र अपने सीमित साधनों के द्वारा आर्थिक विकास की ऊँची दर तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वे आधार भूत कृषि उद्योग का विकास न कर लें। डेविस जैसे अर्थशास्त्री ने भी कहा है कि “ कृषि कोई असाधारण रूप से मौलिक क्रिया नहीं है तथा किसी राष्ट्र की समृद्धि मुख्य रूप से अन्य घटकों जो कि कृषि कार्य करने के अतिरिक्त है, पर निर्भर करती है”।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित है। अपने सीमित साधनों के कारण ग्रामीण लोगों को किसी न किसी रूप में नगरीय समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। वस्तविकता यह है कि अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन नियोजित ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण समाज के आर्थिक समाजिक ढाँचे में परिवर्तन लाना जिससे कि आर्थिक ढाँचे सुदृढ़ हो सके। और ग्रामीणों के रहन-सहन का स्तर अच्छा और प्रगतिशील बन सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में कुछ विशेष व्यक्तियों और विभिन्न जातियों का महत्पूर्ण योगदान है। सम्पूर्ण ग्रामीण आर्थिक ढाँचा कृषि और कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों पर आधारित है। ग्रामीण आर्थिक तंत्र में

जमींदार या सामंत लोग, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण, कारीगर, सेवक आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वों को स्पष्ट करते हुये कोल एवं हूवर ने कहा है कि "सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है तो वह अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा।¹

कृषि की बढ़ती हुई उत्पादकता से औद्योगिक विकास में अनेक तरह से सफलता प्राप्त होती हैं कृषि उत्पादकता में वृद्धि प्रत्येक दशा में सामान्य आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी है।

प्रो लुईस, जैकब वाइनर तथा किण्डलवर्जर जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकास प्रक्रिया में कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू मांग की पूर्ति आत्म निर्भरता एवं निर्यात वृद्धि जैसी आधारभूत समस्याएँ कृषि ग्राम विकास से ही हल की जा सकती हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'कृषि विकास का अर्थ होता है कि कृषि जब कृषि का विकास करती है तब सम्पूर्ण आर्थिक प्रगति स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती है।'

वास्तव में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की कुल भूमि का 2.5 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है भारत की स्थिति को देखें तो लगभग 60 प्रतिशत लोगों को कृषि ही रोजगार दे रही है। भारत को निर्यात क्षेत्र में कृषि का हिस्सा 2011-12 के 12.81 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 13.8 प्रतिशत हो गया है। भारत दुनियाँ में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहनों की खेती करने वाला देश है। जबकि कपास के क्षेत्र में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर हर किस्म विकसित की गई है।

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।

1. कृषि एक मुख्य व्यवसाय के रूप में — हम भलीभाँति जानते हैं कि 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कृषि व्यवसाय में लगे हुये हैं। उनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है अच्छी और खराब फसल का सीधा प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ता है कृषि आधारित उद्योगों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। खेतों की बुवाई जुलाई तथा कटाई के समय खेतिहर मजदूर की मांग बढ़ जाती है पर पैदावार के दौरान किसान खाली ही रहता है।

2. राष्ट्रीय आय में महत्व — भारत के सफल घरेलू उत्पाद में 2012-13 में कृषि का योगदान 13.7 प्रतिशत रहा कृषि अनुसंधान के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 684 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसे 2002-03 के दौरान 775 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

3. खाद्यान्न पूर्ति — भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पायेंगे। भारत खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्म निर्भर हो गया है किन्तु कभी-कभीसूखा, बाढ़ पाला आदि आदि के कारण फसलें नष्ट भी हो जाती है। वर्तमान में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 2.5 करोड़ परिवारों को सरकार अनाज पहुँचाने का प्रयास कर रही है।

4. औद्योगिक विकास — भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय पर अनेक कुटीर उद्योग धन्धे निर्भर करते हैं जैसे अवकाश के समय रस्सी बनाना, चटाई बनाना, सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि। बड़े पैमाने के उद्योग में भी कृषि का विशेष महत्व रहा है।

5. विदेशी व्यापार – विदेशी व्यापार में कृषि पदार्थों का विषेश महत्व रहा है प्रथम योजना काल में भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का मात्र 41 प्रतिशत द्वितीय योजना में 42 प्रतिशत तृतीय योजना में 45 प्रतिशत चतुर्थ में 45 प्रतिशत पंचम 47 प्रतिशत और छठी योजना में 47 प्रतिशत योगदान रहा है। वर्तमान योजनाओं में योगदान बढ़ रहा है।

6. जीविकोपार्जन के साधन के रूप में – कृषि और इसमें जुड़े हुए अनेक छोटे बड़े कार्य एवं उद्योगों से देश के 65 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। अनेक व्यक्तियों को कृषि व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है जैसे खेत को जोतने बोन और काटने वाले श्रमिक, सिंचाई करने वाले व्यक्ति, अनाज को साफ करके मण्डी तक पहुँचाने वाले व्यक्ति, कुटीर-उद्योग धन्धो से जुड़े हुये व्यक्ति , व्यवसायिक फसलें, प्रोसेसेड फूड, उर्वरक व बीज व्यापार से जुड़े लोग ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण चौपाल आदि किसी न किसी रूप में कृषि व्यवसाय में वधे हैं।

7. यातायात व्यवसाय— यहाँ के यातायात साधनों को कृषि व्यवसाय से जितनी आय होती है सम्भवतः अन्य उद्योगों से नहीं होती है। ट्रक, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, मालगाड़ी आदि कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक है।

अतः हम कह सकते है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था पर सम्पूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। यदि ग्रामीण भारत में औसतन सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया गया तो निश्चय ही भारत प्रगतिशील राष्ट्र एक अद्वितीय एशियाई शक्ति के साथ में उभरेगा। अतः हम कह कहते है कि भारत में कृषि अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि को एक जीने का तरीका भी सिखाती है।

परन्तु भारत में कृषि का इतना अधिक महत्व होने के बाबजूद भी वर्तमान स्थिति बड़ी ही सोचनीय है।

डॉ कलाउस्टन के अनुसार – “भारत में कुछ गिरी हुई या पिछड़ी हुई जातियाँ और कुछ पिछड़े हुये उद्योग भी तथा दुर्भाग्य से कृषि इन उद्योगों में से एक है² वर्तमान में आज कृषक अत्यन्त समस्याओं से जूझ रहा है।

उत्पादन प्रणाली पर प्रभाव – उत्पादन प्रणाली की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक घटनाओं का एक दस्तावेज है जो श्रमिकों के विभिन्न युगों की शोषण के यथार्थ को व्यक्त करती है।

कार्लमार्क्स – का सम्पूर्ण दर्शन यथार्थ जगत की घटनाओं पर आधारित है इसके सिद्धान्तों के केन्द्र में उत्पादक प्रणाली, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है। कार्लमार्क्स का दृढमत है कि उत्पादन के साधनों और उसकी शक्ति में परिवर्तन के साथ ही अर्थिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुवादी दृष्टि से किया गया है और तथ्यों के संकलन और विश्लेषण मे वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है।

कार्लमार्क्स के शब्दों में – “सामाजिक सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है नवीन उत्पादन में परिवर्तन के प्राप्त होने पर व्यक्ति अपनी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करते हैं और अपनी उत्पादन प्रणाली और जीविकोपार्जन की प्रणाली परिवर्तित करने से वे अपने सब प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों को बदल देते हैं। जब हाथ की चक्की थी तब समान्तवादी समाज था, भाप से चलने वाली चक्की वह समाज बनाती है जिसमे प्रभुत्व औधौगिक पूंजीपति का होता है³

कार्लमार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों, सम्बन्धों और प्रणाली का अध्ययन करते हुये बताया कि मुनष्य को

जीवित रहने के लिए सर्व प्रथम कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और कुछ जरूरी चीजे। यह सभी चीजे उसको प्रकृति के द्वारा बनी बनाई नहीं मिलती है बल्कि इन वस्तुओं का वे उत्पादन करते है हम कह सकते है कि मानवीय जीवन और अस्तित्व का आधार हमेशा भौतिक उत्पादन रहा है। यह कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इस तरह भौतिक चीजों का उत्पादन अपरिहार्य है।

वास्तव में आर्थिक उत्पादन समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारक और साधन है। इस तरह आर्थिक उत्पादन का कारण एक केन्द्रीय अवधारणा है जिसके प्रभाव से समाज में अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वास्तव में उत्पादन की प्रणाली सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती है। अतः कार्लमार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली केन्द्र में है। इसकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं है। उत्पादन करने में उत्पादन की शक्तियाँ भी प्रमुख होती हैं उत्पादन की शक्तियों को परिभाषित करते हुए मारिस कॉन फोर्थ ने कहा है कि “उत्पादन करने के लिए उत्पादन के उपकरण आवश्यक होते है जैसे औजार, मशीने, यातायात के साधन आदि किन्तु यह उपकरण स्वयं अपने द्वारा कोई उत्पादन नहीं करते हैं। जनगण ही उनका निर्माण करते है और प्रयोग करते है। जनगण के उत्पादन के उपकरण बनाने तथा उत्पादन की शक्तियों में (i) उत्पादन के उपकरण और (ii) उत्पादन अनुभव तथा कुशलता से लैस जनता जो उन उपकरणों का प्रयोग करती है सम्मिलित होते है।”

अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते है कि मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन में उत्पादन शक्तियों का सम्बन्ध और प्रणाली की अवधारणा केन्द्रीय है। उत्पादन प्रणाली उत्पादन शक्ति सम्बन्धों से बनती है। सामान्य तौर पर मार्क्स ने इन्हें सामाजिक प्रक्रिया के मुख्य निर्धारक तत्व माने है।

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का उत्पादन पर हमेशा प्रभाव पड़ा है निरन्तर विकास की तरफ अग्रसर अर्थव्यवस्था आज भी उत्पादन प्रणाली में प्रभाव डाल रही है। भारत में कृषि अर्थ व्यवस्था का उत्पादन प्रणाली पर आज भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि का पिछड़ापन एवं निम्न उत्पादकता के अनेक कारण है जिसमें कुल कारणों का उल्लेख हम निम्नप्रकार कर सकते है –

1. खेतों का छोटा तथा दूर-दूर होना।
2. प्राचीन एवं अवैज्ञानिक कृषि पद्धति।
3. खेतों में स्थायी उन्नति की कमी।
4. पानी के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता।
5. भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव।
6. उत्तम बीजों का अभाव
7. खाद का अभाव।
8. दुर्बल पशु भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
9. फसलों के रोग एवं शत्रु।
10. पूंजी का अभाव।
11. किसानों का ऋण ग्रस्त होना।

12. किसानों की निरक्षरता एवं रूढ़िवादिता।
13. भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था।
14. फसलों का खेती पर अत्यधिक निर्भरता।
15. भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी।
16. अस्वस्थ किसान।
17. यातायात के साधनों की कमी।
18. नियोजन तथा नियमन का अभाव।
19. वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी।
20. निरूत्साहक ग्रामीण वातावरण।

आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो हमारी उत्पादन प्रणाली को प्रभावित करते हैं जिनके कारण उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता है। हमें उत्पादन प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अर्थ व्यवस्था को निश्चित रूप से विकसित करना पड़ेगा और हमें निम्न उपायों के द्वारा उत्पादन प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे जैसे –

1. चकवन्दी और सहकारी खेती।
2. ग्रामीण उद्योगों का विकास।
3. जनसंख्या की वृद्धि पर रोक।
4. सिंचाई के साधनों का विकास।
5. नवीन कृषियंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा।
6. खेती की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग।
7. पशुओं की दशाओं में सुधार।
8. फसलों को कीटाणुओं से बचाना।
9. उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग।
10. खाद सुविधाओं की व्यवस्था।
11. शिक्षा का प्रसार।
12. कृषि उपज के विज्ञापनों की व्यवस्था।
13. डेयरी फार्मिंग का विकास।
14. भूमि संरक्षण।
15. कृषि योग्य वेकार भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाना।
16. सहकारी आन्दोलनों का प्रचार प्रसार।
17. कृषि अनुसंधान।

इस प्रकार कृषि उत्पादन प्रणाली में उपर्युक्त प्रयासों द्वारा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का उत्पादन प्रणाली पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अच्छी कृषि प्रणाली निश्चित रूप से ग्रामीण खुशहाली का कारण बनती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक है। जबकि खराब कृषि ग्रामीणविपन्नता, कृषकों की ऋणग्रस्तता एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की नकारात्मक प्रगति की ओर बढ़ाती है। कृषि की सम्पूर्ण समृद्धि देश की समृद्धि का प्रतिबिम्बित करती है। और इसकी मन्दगामीता सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर मन्दगामी प्रभाव डालती है।

अतः हमें भारत में कृषि अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक सुदृढ करने के लिए प्रयास करने पडेगें। तभी उत्पादन प्रणाली पर अच्छे प्रभाव पडेगें।

सन्दर्भ सूची :

1. डॉ मिश्र जयप्रकाश – कृषि अर्थशास्त्र संस्करण 2013 साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृष्ठ 18।
2. डॉ कालउस्टन – कृषि अर्थशास्त्र पाटनी आर0एल0 संजीव प्रकाशन मेरठ पृष्ठ 59 दशम संस्करण।
3. अग्रवाल डॉ अंकित – भारत में ग्रामीण समाज पृष्ठ 109।
4. पाटनी आर एल – कृषि अर्थशास्त्र संजीव प्रकाशन मेरठ संस्करण 2010।
5. सुन्दरम के पी दत्तरुद्र – भारतीय अर्थव्यवस्था।

